

न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर०ए०एस० अति० सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 83/2022/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड

दायरा दिनांक 29.3.2022

अन्तर्गत धारा: 76 राज०भू राजस्व अधि०, 1956

उनवान

देवीलाल पुत्र मोतीलाल जाति कुम्हार निवासी मोल्यक्याखुर्द तहसील बकानी जिला झालावाड राज०।

...अपीलार्थी

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार बकानी जिला झालावाड राज०।

... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री नरपत सिंह राजावत अभिभाषक -अपीलार्थी
पैरोकार सरकार-रेस्पोंड

::निर्णय::

दिनांक 22.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि० नं० 153/अपील/2020 अन्तर्गत धारा 75 राज० भू राजस्व अधिनियम बउनवान देवीलाल बनाम राज० सरकार जरिये तहसीलदार बकानी में पारित निर्णय दिनांक 1.3.2021 (संक्षेप में अपीलार्थी निर्णय) के विरुद्ध द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

- 1 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं, कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बकानी द्वारा दिनांक 16.9.2020 को निर्णय पारित कर ग्राम मोलक्या खुर्द की आराजी खसरा नं० 490/7 रकबा 0.01 है० किस्म चारागाह पर कच्चा मकान द्वारा कब्जा करने का अतिक्रमी मानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 03/-रुपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड में पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 1.3.2021 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.3.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि नियमों एवं संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। अपीलार्थी ने विवादित आराजी से नाजायज कब्जा छोड़ दिया है अपीलार्थी का उक्त विवादित आराजी के किसी भी भू भाग पर वास्तविक व भौतिक रूप से अतिक्रमण अथवा नाजायज कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाक्याती एवं कानूनी प्रक्रियाओं की गलतियां कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन होने से आवागमन बन्द होने से समय पर निर्णय के लिये आवेदन नहीं कर सका। अनलॉक होते ही दिनांक 15.7.21 को नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 17.7.21 को नकल प्राप्त हुई उसके बाद बिना किसी देरी के अपील पेश की गई अतः अपील पेश करने में हुई क्षम्य की जाकर जानकारी व नकल निर्णय के दिन मुजरा कर अपील को अवधि मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 1.3.2021 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।
- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड को जरिये सम्मन आहूत किया गया। परीक्षण/अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पोंड पैरोकार सरकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि नियमों एवं संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। अपीलार्थी ने विवादित आराजी से नाजायज कब्जा छोड़ दिया है अपीलार्थी का उक्त विवादित आराजी के किसी भी भू भाग पर वास्तविक व भौतिक रूप से अतिक्रमण अथवा नाजायज कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाक्याती एवं कानूनी

अति. सं. अनुसूच
कोटा

रीडर (पेशकार)

- प्रक्रियाओं की गलतियां कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अंत में अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक होने से अपील अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण पर विचार कर अपील स्वीकार की जावे।
- 4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।
- 5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः अपील पर गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निस्तारित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने प्रार्थना एवं शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया है ना ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली में कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।
- 6 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया। बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार बकानी ने निर्णय दिनांक 16.9.2020 को ग्राम ग्राम मोलक्या खुर्द की आराजी खसरा नं0 490/7 रकबा 0.01 है0 किस्म चारागाह पर कच्चा मकान द्वारा कब्जा करने का अतिक्रमी नानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 03/-रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित जिसकी प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड में पेश की गई जिसे न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड ने निर्णय दिनांक 1.3.2021 को खारिज किया गया।
- 7 अपील प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि "जेरअपील निर्णय विधि नियमों एवं संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है क्योंकि अपीलांट ने विवादित आराजी से नाजायज कब्जा छोड़ दिया है अपीलांट का उक्त विवादित आराजी के किसी भी भू भाग पर वास्तविक व भौतिक रूप से अतिक्रमण अथवा नाजायज कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाकयाती एवं कानूनी प्रक्रियाओं की गलतियां कर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है"। अपीलांट के उपरोक्त तर्क के परिपेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि वादग्रस्त अतिक्रमित आराजी किस्म चारागाह है जो पशुओं के चराई के लिये काम आती है तथा ऐसी चारागाह भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 के अन्तर्गत प्रतिबधित भूमि की श्रेणी में आती है एवं ऐसी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाना जनहित में नितांत आवश्यक है। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में इसी वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल नं0 1213 निर्णय दिनांक 4.10.2019 से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था अस प्रकार अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ देने का कथन किया है किन्तु अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसे कोई आधार अभिलेख साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड़ देने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो। अतः अपीलांट का कब्जा छोड़ने संबंधी कथन समुचित आधार अभिलेख के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलांट कोई विधिक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते हैं। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट बलहीन होने से खारिज की जाती है।
- 8 निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अतिरिक्त संभारिय
कोटा